

gas in Cauvery, we have found gas in Krishna and Godavari, and if the Southern gas grid is created, it will link all the four Southern States and avoid wastage of this precious national resource. Therefore, I would like to know from the Minister because now we are having some continuity—he also "hails from the South"—as to what is the present position of a Southern gas grid.

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Sir, as regards the first part of the hon Member's supplementary, gas flaring, of course, is a national waste. But we have a time-bound programme including a Rs. 7,500 crore World Rank project by which we hope to achieve zero-gas flaring or otherwise...

SHRI MURASOLI MARAN: By when?

SHRI S. KRISHNA KUMAR: ... Avoid this phenomenon in the next four to five years.

As regards the second part of the question, the need for a Southern gas grid let us say National gas grid has been voiced from many quarters. An Inter-Ministerial Committee is looking into the whole issue and its feasibility. They have been given certain terms of reference, and their Report is awaited.

MR. CHAIRMAN: Question No. 2.

Purchase of Westland helicopters

*2. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer in the answer to Unstarred Question 944glven in the Rajya Sabha on 29th July, 1991 and state:

(a) the number alongwith the year of purchase of each Westland Helicopter Corporation of India Limited; and

(b) what is the amount of foreign exchange involved in their purchase?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI M.O.H, FAROOK): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House-Statement

(a) The contract for purchase of 21 Westland W-30 helicopters was signed in March, 1986. The helicopters were received in India as per following details:—

Year	No. of helicopters received
1986	5
1987	12
1988	4
Total	21

(b) The Foreign Exchange cost of acquisition of 21 helicopters, spare engines, ground support equipment and engine test bed was £ 70 million equivalent to Rs. 141.53 crores. Or this, £ 65 million (Rs. 130.91 crores) was covered by an ODA Grant.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति जी, इस प्रश्न पर कई बार पहले भी चर्चा हो चुकी है। राज्य सभा में भी पहले यह प्रश्न उठाया जा चुका है। मंत्रीजी ने जवाब भी दिया है, किन्तु लगता यह है कि इस सवाल को रहस्यमय तरीके से, इसका उत्तर ठीक तरीके से न लेकर, छिपाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस प्रश्न के माध्यम से जो मैं पूछ रहा हूँ उसका स्पष्ट उत्तर दें और जो आमकर्मियों लोगों में इस सवाल पर फैला ही गया है, उनका समाधान करने के लिए पूरे तब्य सदत के सामने रखें।

महोदय, मेरा इसमें पहला पूरक प्रश्न यह है कि (क) क्या यह सच है कि तीन एक्सपर्ट कमेटीज ने यह रिपोर्ट दी थी कि यह हेलीकॉप्टर्स न खरीदें जाएँ। इसके बाद भी सरकार ने यह हेलीकॉप्टर्स खरीदे। अगर यह रिपोर्ट के बावजूद

खरीदे हैं जो कि विपरीत रिपोर्ट थी कि यह न खरीदे जायें तो इसमें सरकार को क्या व्यवस्था थी? यह मेरे पहले प्रश्न का (क) भाग है और (ख) भाग यह है कि क्या हम हैलीकाप्टर्स को बनाने वाली जो वेस्ट लैंड कम्पनी हैड्रसकी क्या यह स्थिति थी कि यह कंपनी दिवालियापन के कमार पर थी, उसको बचाने के लिए और यू० के० के प्रेशर में हमारी सरकार ने यह हैलीकाप्टर्स खरीदने स्वीकार कर लिए? मेरे पहले पूरक प्रश्न का भाग (ग) यह है कि क्या हमने राजनीतिक स्तर पर या अन्य किसी स्तर पर किसी मिडिल मैन को लाभ पहुंचाने के लिए यह सारी डील की है? इसके अंदर हम लोगों ने किसके हित को ध्यान में रखकर यह सारी डील की है? मैंने इस पहले पूरक प्रश्न में तीन बातें पूछी हैं इनका मंत्री महोदय जवाब दें तो मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछूंगा।

SHRI M. O. H. FAROOK: Sir, in this transaction, the whole thing is a grant. The British Government has given 70 million pounds equivalent to Rs. 141.53 crores as grant.

MR. CHAIRMAN: Is it grant or loan?

SHRI M. O. H. FAROOK: It is all grant. It is 65 million pound grant.

MR. CHAIRMAN: So, our cost is only 5 million.

SHRI M. O. H. FAROOK: Yes. Our cost is 5 million. Afterwards, when (hey found that there is some defect in operation they gave 10 million more as grant for operation. So, there is no question of ourselves having paid.

MR. CHAIRMAN: You have not paid any money?

SHRI M. O. H. FAROOK: No, Sir.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव त्रिधया) : महोदय, मैं आपके पहले प्रश्न के बारे में कहना चाहूंगा

कि कुछ एक्सपर्ट कमेटीज नियुक्त की गयी थी और उन्होंने भी इसका आकलन किया। उनकी भी रिपोर्ट पेश की गयी। उसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी इसका पूरा जायजा लिया और यह तय किया गया कि यह वेस्ट लैंड हैलीकॉप्टर्स के लिए क्योंकि 65 मिलियन पाउंड्स जैसा कि मंत्री महोदय बर्ता चुके हैं, आउटर इट ग्रांट्स के रूप में मिल रहा है, उसके अलावा 10 मिलियन पाउंड्स और ऑपरेशन एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है। और कोई भी हमारी तरफ से खर्चा नहीं होगी, मत्र 5 मिलियन पाउंड्स का खर्चा होगा, इसलिए तय किया गया कि टेक्नो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर इस हैलीकॉप्टर्स का खरीदा जाए माने लिया जाय।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Sir, the case is...

MR. CHAIRMAN: No, Mr. Gurupadaswamy...

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I am not asking question. I just want to draw his attention... (Interruptions).

श्री कृष्ण लाल शर्मा : महोदय, मैं मंत्री महोदय से अपना दूसरा पूरक प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि तीन एक्सपेंडिचर हुए। एक वेण्णी देवी में हुआ, फिर एक नर्थ ईस्ट में हुआ और एक जुहू में बंबई में हुआ, लेकिन पवन हंस लिमिटेड ने इसको बार बार अपग्रेट करने की कोशिश की। अखिर, यह रिस्क क्यों ली गयी? य-जानते हुए भी कि यह हैलीकॉप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं और इस तरह के तीन सीरियस एक्सपेंडिचर होने के बावजूद पवन हंस लिमिटेड को किस की डायरेक्शंस थी, क्या गवर्नमेंट की थी, किस की थी?

इसका "क"। दूसरा "ख" यह है कि अब इसके फाइनल डिस्पोजल के बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है? यह जो 21 हैलीकॉप्टर ग्राउण्ड हैं गए और सरकार

ने वह दिया कि फाइनेली, बी हेव टेकन ए डिजिजन कि भाई, प्राउड हो गए हैं, तो इसको डि.इनली क्या डिस्पोज आफ कर रहे हैं या रिसैल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं ? एक यह प्रश्न है । फिर "ग" यह है कि क्या इसके कारण से, आपने तो वह दिया कि उनकी ग्रांट से हमको मिले हैं, क्या हमें और कुछ लोसेस इन्कर करने पड़े ? जैसे यह हेलिकोप्टर हम उपयोग करने वाले थे थो० एन० जी० सी० के अपरेशन के लिए और यह हेलिकोप्टर हम नहीं दे सके थो०एन०जी० सी० को और उनकी और एक्सपेन्सेज इन्कार करने पड़े । इसके बावजूद दूसरे देशों से और इमिडिएट, अजेंट कुछ रिक्वायरमेंट रखा, इस डील के कारण से यद्यपि यह डील, जैसा आपने कहा ग्रांट से हल हो गया है । लेकिन, इसकी वजह से क्या और कुछ लोसेस इन्कर करने पड़े हैं ? अगर करने पड़े हैं तो कितने हैं ? इसकी जानकारी भी दी जाए ।

श्री सभापति : अब, और उसके आगे तो नहीं है ? "घ" "ङ" तो नहीं है ?

श्री कृष्ण लाल शर्मा : नहीं, बस इतना है ।

SHRI M. O. H. FAROOK: It is true that there have been three accidents; one in August 1988, another in February 1989 and the third in December 1989. The specific clause of this grant is that this helicopter has to be purchased from them only, and this was the specific clause for grant for this specific helicopter. Therefore, we had no other option... (Interruption).

श्री सभापति : यह वह रहे हैं, दान की माय के दांत नहीं देखे जाते ।

श्री प्रमोद महाजन : कोई मृत्यु दान में दे दे तो वह स्वीकार थोड़े ही हो सकता है ।

श्री सभापति : अरे भाई, दान तो यह स्वीकार कर ही लेना चाहिए । मृत्यु ही तो मृत्यु ही सही ।

SHRI M. O. H. FAROOK: In view of the defects which have been found, we are thinking of disposing of these helicopters and various ways and means are being found by the Ministry.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सर, आपने यह नहीं बताया कि एक्सिडेंट होने के बाद इसको दुबारा अपरेट करने की एफर्ट्स क्यों की गई ?

श्री माधवराव सिधिया : सर, कुछ जो दुघटनाएँ हुईं, उसमें से एक अपरेटर एरर के कारण हुई, पहली दुघटना जुलाई 1988 में अपरेटर एरर के कारण हुई थी और उसके बाद टेक्नीकली फाल्ट्स के कारण भी दो दुर्घटनाएँ हुईं । इस बीच दिसंबर, 1989 में हुसैनी कमेटी नियुक्त की गई कि पूरी तरह से जांच करे कि इसमें क्या तकनीकी खामी है, क्या कमी है या हमारी मॉडिनेन्स की कोई समस्या है, प्रोब्लम है । तो हुसैनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मारच 3, 1990 में दी थी और तब तक यह एयर-क्राफ्ट उड़ रहे थे । उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन के भी सुझाव रख गए कि इसमें कुछ इंजन और टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन में भी कुछ मॉडिफिकेशन करें । तो चर्चाएँ चल रही थी वैस्टर्न के साथ । इस बीच फिर स एक ग्रांट एक्सिडेंट हुआ और उसके बाद हमन प्राउन्ड किया ।

SHRI SURESH KALMADI: I had warned many times on the floor of this House against the purchase of Westland helicopters. Even, at that time I had said that even if you are getting these helicopters free, please don't touch them.

I would like to know whether the Westland company has honoured all its commitments which were made to the Indian Government at that time. I would further like to know as to what has been the outflow in foreign exchange on account of spares and maintenance which the Indian Government had to bear till date. I would also like to know whether because of

these accidents, which I hear are due to engines failing, or whatever, they sent a team, or whether they have been shirking their responsibility, and in that case whether the Indian Government is going to take any legal action against the company. The hon. Minister said that they are going to dispose of the helicopters. I would like to know whether they are going to call for global tenders or how they are going to dispose them of, or whether they are selling it as scrap.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: With regard to foreign exchange outflow till date, I will have to get full details and send it to the hon. Member.

SHRI SURESH KALMADI: It is a very big amount and I am surprised to note, that the Ministers were not properly briefed by the officer and the amount of foreign exchange which has gone into this is more than the cost of the aircraft.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: What was your first question? Do you want to know how are we going to dispose them of?

SHRI SURESH KALMADI: My most important question is about the commitment.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: As far as the commitment is concerned, the commitment was for the supply of 21 helicopters. That commitment was fulfilled. The second commitment was for an extra grant of 10 million pounds. That commitment was also fulfilled. Subsequently, the technical defects were noticed and the Hussaini Committee also came up with certain recommendations for modifications. As far as the technical parameters are concerned, I must admit that Westland took a long time about it. Not only the Westland but Rolls Royce also took a very long time about it. Since the crash took place, we grounded the whole thing and we have decided not to operate it, in any case.

SHRI SURESH KALMADI: Are you taking legal action, against West-land? We have paid a fabulous amount. It is a camouflage.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: We can take legal action only- under the terms of the agreement. Under the terms of the agreement, it is unlikely that we have grounds for legal action. The third question which the hon. Member asked, was. What are we going to do in the future? We are examining various options and soon we would be taking a decision and we would be putting; it up to the Cabinet.

SHRI SURESH KALMADI: Are you going to- sell it as scrap by weight?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: The Minister of State has made a very astounding remark that the Government of India had to get these helicopters because there was no other option. I marked these words. Please look into the records. I have written, here what he said. Then the Minister said that these helicopters were supplied under grant and a large element of grant was there. My question is whether these grants— it may be aid or it may be grant— should be utilised in such a reckless manner without looking into the project itself: These helicopters have been purchased under an agreement between the Government of India and the Government of U.K. At that time, there was a lot of pressure exerted on the Government of India by the U.K. The then Prime Minister—I do not want to mention her name— exerted all pressures on the Government of India to purchase these helicopters. At that time, the Government of India did not look into the whole thing regarding the technical feasibility and the technical aspects of these helicopters: As a result, we have incurred a heavy loss. The oil sector itself was using those helicopters and we suffered a lot on account of these helicopters. Now, all the helicopters have been grounded. My second question is whether the Government

of India should not have exercised control over the utilisation of grant. It may be a grant but it is still money. This grant may have been utilised for some other purpose.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Let me first correct the impression of the hon. Member. I do not know if my hon. Minister of State used the word 'no other option'. If he did, he obviously meant there may have been other options but this was an outright grant. We were not spending any money at all except the 5 million pounds that we were going to spend on some spares. Apart from that, we are not spending any money. I think, in that context, what the Minister meant when he used the words 'no option' was not that other alternatives were not available to us, but then the outflow would have been much later. As far as what the hon. Member asked about the alleged reckless use of the grant is concerned, there were two committees which went into this and did clear it on technical parameters and also the economic parameters. Whatever the differentiation there was on the economic parameters of operation, that was compensated by the 10 million pounds that was given again as an outright grant against operational loss. Therefore, there were two Committees which had cleared this helicopter subsequently.

श्री मोहम्मद सलीम : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा अपने उत्तर में बताया कि यह हमें बाहर से अनुदान के तौर पर मिला था। लेकिन यह भी पब्लिक हमें के लिए लायबिलिटीज बना है। जो फोरैन एक्चेंज दिशा गया था बैस्टलीड खरीदने के लिए उसके लिए पब्लिक हमें को काफी इक्विवैलेंट डिफॉजिट करना पड़ा गवर्नमेंट के एकाउंट में और वह पूरा नहीं कर पाये, उसके लिए अजब भरना पड़ रहा है जिसके कारण पब्लिक हमें खुद-ब-खुद सूखा जा रहा

है, मरा जा रहा है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि उन्होंने पार्ट-बी के जवाब में यह कहा है कि—

"The foreign exchange cost of acquisition of 21 helicopters, spare engines, ground support equipment and engine test bed was 70 million pounds equivalent to Rs. 141.53 crores."

जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट का उसके मुताबिक इनिशियल रैजिस्ट्रार स्पेर्स तमाम के साथ दिये, लेकिन उस वक्त जो एंटीपेट दिया गया था स्पेर्स के लिए उसके बावजूद बाव में यह चेखा गया कि यह स्पेर्स काफी महंगे हैं। इनिशियल स्नोस हा, वही है और प्राइडिंग करना पड़ रहा है, ता बाव में और भी स्पेर्स खरीदने पड़े। उसके लिए जो फोरैन एक्चेंज एमाउंट इवें करना पड़ रहा कितना था और किस के अनुदान मिलना था और यह कि ज. प्राइम सप्लायर्स हैं, मॉडर्नकरण है उनसे खरीदा गया य बीच में मिलाने से तो वह कौन मिलाने था ?

श्री माधव राव सिधिया : सर, अजब का जो सबल ही नहीं उठता। अभी अजब राइट गारंटी था तो अजब का तो सबल ही नहीं उठता; जो पूरा एमाउंट अजब 65 मिलियन पाउंड का और 10 मिलियन पाउंड ऑपरेशनल खोस के एगोस्ट, वह तो अजब राइट गारंटी था, उस पर कोई अजब तो था नहीं। जहाँ तक स्पेर्स का संबंध है, मानरेटिल मेंबर कलमाही सहाय ने भी यह बात पूछी थी, उसके बारे में मैं पूरे डिटेल्स जो भी अभी तक अजब फ्लो हुआ है, हर एक डिटेल्स मैं नोम्बर्स को देने के लिए तैयार हूँ अगर वह चाहे हैं।

Coal supply to power plants In Madhya Pradesh

*3. SHRI SURESH PACHOURI: Will, the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State of Madhya Pradesh is not be-